

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 11 नवम्बर, 2009

विषय:-मा0 सिविल जज (जू0डि0) न्यायालय, तहसील गंगोलीहॉट, जिला पिथौरागढ़ के भवन निर्माण हेतु कुल 0.040 है0 भूमि, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, तहसील गंगोलीहॉट, जिला पिथौरागढ़ में मा0 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय के भवन निर्माण हेतु कुल 0.040 है0 भूमि, जो वर्तमान में राज्य सरकार की श्रेणी 9-3ड बंजर काविल आबाद की है, को शासनादेश संख्या-49 / XVIII(II) / 2009, दिनांक-09.10.09 द्वारा निःशुल्क पट्टे पर आवंटित किये जाने विषयक उक्त शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए, वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260 / वित्त अनुभाग-3 / 2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अन्तर्गत न्याय विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
 - 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
 - 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०संख्या-153 /समदिनांकित/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- 4- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय।
- 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव।